भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2403
बुधवार, 22 मार्च, 2023 (1 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

कर्नाटक में सहकारी समितियां, पीएसीएस और एमपीसीएस

2403 श्री नारायण कोरागप्पाः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) सहित सहकारी समितियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण का जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि क्या है; और

(ग) कर्नाटक की प्रत्येक पंचायत में नई बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति (एमपीसीएस) के गठन का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकारी समितियों के पंजीयक, कर्नाटक से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य में 6,040 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) सहित विभिन्न क्षेत्रकों में लगभग 45,926 सहकारी समितियां हैं । पैक्स सहित सहकारी समितियों की जिला-वार सूची **अनुबंध** पर संलग्न है ।

2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कर्नाटक राज्य सहित देश भर के कार्यशील पैक्स/LAMPS को कंप्यूटरीकृत करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वयनाधीन है । केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयों (PMUs) की स्थापना हो गई है और नाबार्ड द्वारा सॉफ्टवेयर विकास का कार्य भी आरंभ हो चुका है । परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण को पूरा करने की लक्षित तारीख 31.03.2025 है और हैंडहोल्डिंग सहायता देने की अंतिम तारीख 31.03.2027 है ।

नाबार्ड द्वारा कर्नाटक राज्य में 5,491 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव की सिफारिश की गई है और कर्नाटक राज्य को हार्डवेयर की खरीद, सहयोग तंत्र की स्थापना, इत्यादि के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्सेदारी की पहली किश्त के रूप में 25.45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

कर्नाटक राज्य में कंप्यूटरीकरण हेतु सिफारिश की गई पैक्स की जिला-वार संख्या का ब्यौरा भी **अनुबंध** पर संलग्न है ।

सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां बनाई है जिससे पैक्स अपने कार्यों में विविधता लाकर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में परिवर्तित हो सके । इन आदर्श उपविधियों को दिनांक 05.01.2023 को कर्नाटक राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पैक्स द्वारा उसे अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियम के अध्यधीन अपनाने हेतु परिचालित कर दिया गया है । ये आदर्श उपविधियां पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, खाद्यान्न भंडारण, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीज़ल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कॉमन सेवा केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान (FPS), आदि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करेंगे ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर आगामी पांच वर्षों में कर्नाटक राज्य सहित देश भर के प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करने के लिए दो लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी या मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

******

अनुबंध

कर्नाटक राज्य में पैक्स की जिला-वार सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	सहकारी समितियों की संख्या	पैक्स की संख्या	प्रथम चरण में कंप्यूटरीकरण हेतु लिए गए पैक्स की संख्या
1	बेंगलूरू शहरी	2776	46	37
2	बेंगलूरू ग्रामीण	1127	78	69
3	रामानगर	1334	101	98
4	बगलकोट	1989	284	265
5	बेलगाम	6111	1318	1156
6	बेल्लारी	1568	197	177
7	बीदर	1305	188	188
8	चिकमंगलूर	616	129	128
9	चित्रदुर्ग	1028	165	149
10	दवनागेरे	1456	181	176
11	हस्सन	1977	228	215
12	धारवाड़	1076	165	152
13	गड़ग	1083	179	160
14	हवेरी	1323	231	227
15	कालबुर्गी	1543	231	179
16	यादगिर	871	108	86
17	कोडागु	342	76	76
18	कोल्लार	1609	104	85
19	चिकबल्लापुर	1575	159	116
20	मैसूरू	2526	201	176
21	चामराजनगर	820	105	103
22	मांड्या	2217	235	227
23	उत्तरी केनरा	941	179	156
24	रायचुर	1288	140	135
25	कोप्पल	829	125	115
26	शिमोगा	1268	176	167
27	दक्षिण केनरा	871	122	121
28	उडुपि	681	57	56
29	तुमकुर	2222	242	230
30	विजयपुरा	1554	290	266
कुल		**45926**	**6040**	**5491**

*****